Visit to Japan by Minister of External Affairs

1676. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Minister of External Affairs paid a visit to Japan in August, 1995;

(b) if so, whether issues on bilateral agreements and other various international issues concerning both the countries were discussed; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (c) Yes Sir. Minister of External Affairs visited Japan in September 1995 at the invitation of the Foreign Minister of Japan and discussed several issues relating to bilateral relations and on other international issues. The Minister called on the Emperor of Japan and met Prime Minister, Foreign Minister and Minister of International Trade and Industry of Japan. He also met members of India Japan Business Cooperation Commitee, members of India-Japan Association India-Japan Parliamentarian Friendship League and Japanese academicians. During the visit, both sides agreed to have a rgular exchange of high level visits. The two sides also agreed to discuss policy towards Asia. During EAM's meeting with MITI Minister, it was agreed that there should be enhanced trade and economic cooperation between the two countries. In this meeting with Japanese corporate leaders, EAM was told that the Japanese Corporations are paying much greater attention to India now. In this meeting with academicians, it was agreed to pursue greater exchanges of academicians and intellectuals between the two sides.

Encouragement to States for Plantation of Valuable Trees

1677. SHRI YEERA NARAYANASWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Central Government have encouraged States like Andhra Pradesh to plant and raise plantations of valuable timber like Rosewood, Sandalwood, etc.;

(b) whether any financial assistance will be given to State Government for raising such plantations of valuable timber; and

(c) if so, the detailed policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Under the 20-Point Programme, afforestation and tree planting activities are undertaken annually throughout the country, including in Andhra Pradesh, keeping in view the availability of funds under the schemes of the Central & State Governments. The species for plantation are determined by the implementing agencies in the States/Union Territories as per the local climatic and soil conditions.

(b) and (c) Financial assistance is given to the State Governments/UTs under the ongoing schemes of the Ministry of Environment & Forests. In undertaking the afforestation and tree planting activities, emphasis is given to the planting of indigenous species that provide fuelwood, fodder, small timber and non-timber forest products to meet the needs of the people.

तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जैसलमेर का कार्यकरण

1678. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जैसलमेर स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कार्यकरण के बारे में जांच कराने की मांग की है; यदि हां, तो सरकार ने इस

संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) विशेषज्ञों के नाम क्या हैं और वे जैसलमेर में इस प्रयोजनार्थ कब से काम कर रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री से ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है।

लखनऊ, आगरा और कानपुर में एल०पी०जी० वितरण प्रणाली

1679. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन तेल कम्पनियों की वर्तमान रसोई-गैस वितरण प्रणाली से उत्तर प्रदेश में विशेषकर लखनऊ, आगरा और कानपुर में उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को गत तीन महीनों के दौरान इन शहरों में रसोई गैस के प्रति सिलिंडर पर अधिक पैसा देने के लिए बाध्य किया गया है;

(ग) क्या कुछ वितरण उपभोक्ताओं को कम वजन वाले एल०पी०जी० सिलिंडरों की आपूर्ति कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समुचित सेवा सुनिश्चित करने और दोषी वितरकों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध देश में वर्तमान एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। लखनऊ, आगरा और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले अस्थायी बैंक लोगों को बढ़ाए गए कार्य-घंटों और अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके और समीपवर्ती क्षेत्रों में भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है।

(ख) सितंबर, 95 से नवंबर, 95 की अवधि के दौरान अधिक कीमत लेने की कोई साबित शिकायत नहीं रही है।

(ग) और (घ) भरण संयंत्रों पर एल पी जी सिलेंडरों के वजन की शुद्धता सुनिश्चत करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित पद्धतियां हैं। एल पी जी भरण संयंत्रों से प्राप्त होने पर डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा एल पी जी सिलेंडर तोले जाते हैं और कम वजन वाले सिलेंडर भरण संयंत्रों को वापस भेज दिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को रीफिल सिलेंडर की सुपर्दगी से पहले डिस्ट्रीब्यूटरों को इसे तौलना होता है ताकि वजन की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही कम वजन के सिलेंडरों की बिक्री से संबंधित विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं। एल पी जी विपणन कंपनियों द्वारा इनकी जांच-पड़ताल की जाती है और यदि शिकायत साबित हो जाती है, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकारों द्वारा भी अपने माप और तौल विभागों के माध्यम से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता से कम वजन वाला सिलेंडर वापस लेकर उसे एक नया सिलेंडर भी जारी किया जाता है।

Security threat to Egyptian Embassy Staff

1680. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the staff of Egyptian Embassy in India is facing threats of terrorist attacks;

(b) if so, whether any request has been received for providing tight security; and

(c) if so, what action has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (c) Under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Receiving State is under an obligation to take all appropriate steps to protect the premises of the Missions, persons of diplomatic agents and private residences occupied by them against any intrusion, damage, disturbance or impairment. The same protection is also given to non-diplomatic staff members.

The Government of India is fully meeting its obligations on this account and appropriate security is being provided to all foreign diplomatic interests as per the requirements of each